

INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
IJH 2020; 2(2): 180-183
Received: 26-06-2020
Accepted: 28-07-2020

अखिलेन्द्र कुमार रंजन
शोधार्थी, विश्वविद्यालय
इतिहास-विभाग, जय प्रकाश
विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार,
भारत

ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योग की गिरावट एवं नया व्यापार पैटर्न

अखिलेन्द्र कुमार रंजन

सारांश

भारत में देशी व्यापारियों के दास्ताँ और जुल्म के जबरदस्त इस्तेमाल से अंग्रेजी ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। लेकिन इस एकाधिकार ने एक बदसूरत आकार ले लिया और भारतीय निर्माताओं के उत्पीड़न का नेतृत्व किया, विशेष रूप से कपास के सामान का। बंगाल के कपास के माल की इंग्लैंड और यूरोपीय बाजारों में काफी मांग थी। आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अंग्रेजी बुनकरों के साथ आगे के अनुबंधों में प्रवेश करेगा, श्यानी, निर्धारित तिथि के भीतर उन्हें निर्धारित राशि के कपड़े की आपूर्ति के लिए दादान (अग्रिम) देगा।

प्रस्तावना

भारतीय उद्योग की गिरावट कंपनी के नौकरों के हाथों में उत्पीड़न का एक नया स्रोत बन गया। कंपनी के प्राधिकार से सशस्त्र कंपनी के नौकरों ने गरीब बुनकरों को, झगड़े के दर्द पर मजबूर करने के लिए, अनुचित समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया।

बुनकरों को उत्पादन की लागत से काफी कम भुगतान किया गया, जिससे बुनकरों को नुकसान हुआ। उन्हें शारीरिक दंड के दर्द पर कंपनी के अलावा किसी अन्य पार्टी के लिए काम करने से भी रोका गया था। कच्चे रेशम के श्रमिक भी उसी नीति के अधीन थे।

आम तौर पर यह माना जाता था कि कई सूती कपड़े और रेशमी कपड़े के कई बुनकर अपने खुद के अंगठे काट लेते हैं ताकि उन्हें कंपनी के लिए बुनाई करने और परिणामी उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए मजबूर न होना पड़े। कहानी को इतिहासकारों ने एक लोकप्रिय आविष्कार माना है। लेकिन इसने निश्चित रूप से उन बुनकरों के डर को अभिव्यक्ति दी, जिन्हें कंपनी के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था, और कंपनी के नौकरों के हाथों उनके दुख और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

बुनकरों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इसकी पुष्टि वर्लस्ट ने की है, जिन्होंने 1767 में बुनकरों की अत्यधिक कमी को संदर्भित किया था क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने इस व्यवसाय को छोड़ दिया था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कंपनी द्वारा सूती और रेशमी कपड़े के एकाधिकार नियंत्रण की बुराइयों और कंपनी के नौकरों द्वारा किए गए अमानवीय उत्पीड़न के कारण कपास और रेशम बुनाई उद्योग बर्बाद हो गया, जो कभी इसके निर्यात के माध्यम से विदेशी सोने की भारी आमद के लिए जिम्मेदार था। उत्पादों। उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कॉर्नवॉलिस के प्रयास निष्ठभावी साबित हुए, क्योंकि पहले से ही अपर्णीय शारारत की जा चुकी थी। बंगाल में बुनाई उद्योग की बर्बादी कंपनी की एकाधिकार नियंत्रण और बुनकरों के अंग्रेजी नौकरों के उत्पीड़न की दो बुराइयों के कारण हुई थी। लेकिन ब्रिटिश निर्मित कपड़े की अनुचित प्रतिस्पर्धा की तीसरी बुराई से खंडहर पूरा हो गया। कपास और रेशम का कपड़ा इंग्लैंड में बेहद लोकप्रिय था और इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में उत्पादित मशीन से बने कपड़े की तुलना में अधिक मांग थी।

लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड को बाजारों की जरूरत थी और ब्रिटिश संसद ने 1700 और 1720 में दो अधिनियमों को पारित करने, या अन्यथा भारतीय कपास और रेशम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर इंग्लैंड में भारतीय कपास और रेशम के सामान के आयात को रोकने के लिए समीचीन सोचा। माल। 1776 में इंग्लैंड और अमेरिका के बीच दुश्मनी, यानी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, नेपोलियन युद्धों के रूप में भी इंग्लैंड और अमेरिका के बीच 1812 में युद्ध हुआ, व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड में बंगाल कपास और रेशम माल का आयात बंद हो गया। ब्रिटिश कालिको प्रिंटर ने बंगाल सरकार से मुद्रित सूती और रेशमी कपड़े के आयात को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमत था और मुद्रित कपास और रेशम के सभी आयात चार साल के लिए रोक दिए गए थे।

इन मनमाने और कृत्रिम तरीकों से ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी निर्माताओं को अपने माल की गुणवत्ता

Corresponding Author:
अखिलेन्द्र कुमार रंजन
शोधार्थी, विश्वविद्यालय
इतिहास-विभाग, जय प्रकाश
विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार,
भारत

में सुधार करने और कंपनी द्वारा किए गए आयात पर शुल्क और माल दुलाई में वृद्धि करने का अवसर दिया। इसने अंग्रेजी निर्माताओं को भारतीय कपास के सामान को अंग्रेजी बाजारों में रेखांकित करने में सक्षम बनाया।

तब यह कंपनी की नीति बन गई कि वह भारत से केवल कच्चे माल के आयात की नीति का पालन करे और भारतीय बाजारों में तैयार माल का निर्यात करे। मैनचेस्टर के कपास के सामान को भारी मात्रा में बंगाल में निर्यात किया गया और बहुत सस्ते दाम पर बेचा गया। भारत में कपास के सामान का अंग्रेजी निर्यात 1786 में 1,200,000 पाउंड स्टर्लिंग का मूल्य था, लेकिन यह 1806 तक 18,400,000 पाउंड स्टर्लिंग तक पहुंच गया। इसके बाद की प्रगति कहीं अधिक अभूतपूर्व थी।

प्लासी के युद्ध से आधी सदी के भीतर बंगाल को उसके सबसे फलते-फूलते उद्योग, यानी सूती और रेशम के वस्त्र उद्योग का कुल बर्बाद हो गया। अनुचित प्रतिस्पर्धा, बंगाल के बुनकरों पर अत्याचार के कारण अंग्रेजी नौकरों और कपास और रेशम उद्योगों के हाथों में पारित अंतर्देशीय व्यापार बर्बाद हो गया। ब्रिटिश संसद के विधानों ने व्यापार और उद्योग को बर्बाद कर दिया जिसने बंगाल को भारत के सबसे समृद्ध मौतों में से एक बना दिया था।

भारतीयों के वर्तमान आर्थिक पिछड़ेपन की उपरोक्त परिस्थितियों में अपनी उत्पत्ति थी, लेकिन बंगाल एकमात्र पीड़ित नहीं था। बंगाल का सच क्या था, आम तौर पर बोलना, शेष भारत का सच था। बंगाल में व्यापार और उद्योग का क्षरण पूरे भारत में अठारहवीं शताब्दी के अंत में हुआ।

आमतौर पर कहा जाता है कि भारत कभी भी औद्योगिक देश नहीं रहा। लेकिन यह इतिहास के तथ्यों के विपरीत है। भारतीय कला और शिल्प का अनादिकाल से भारत की विशाल संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान था। औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत बाद की अवधि में भी जब पश्चिम के व्यापारी साहसी लोगों ने भारत में अपनी पहली उपरिथिति दर्ज की, इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी दर पर, अधिक उन्नत यूरोपीय राष्ट्रों से हीन नहीं था। दोनों भारतीय तैयार माल और प्राकृतिक उत्पादों जैसे मोती, इत्र, डाई-सामान, मसाले, चीनी, अफीम, आदि का निर्यात दूर देशों को किया गया और उसके आयात में तांबा, सोना, जस्ता, टिन, सीसा, शराब, घोड़े, आदि थे।

व्यापार का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में था। जो सोने की बड़ी मात्रा में बाढ़ का कारण बना। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने रोमन साम्राज्य में भारतीय विलासिता के सामानों के उपयोग की एक कड़वी शिकायत की, जिसके कारण पहली शताब्दी ईस्वी में भारत को भारी मात्रा में सोने की निकासी हुई, उत्सुकता से इसी तरह की शिकायत अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। यानी सत्रह सौ साल बाद। भारत में मुख्य उद्योग कपास, रेशम और ऊन का बुनाई था। बंगाल के अलावा, अहमदाबाद, नागपुर, लक-अब, मेरठ सूती उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे, और पंजाब और कश्मीर को विशेष रूप से शॉल और अन्य ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए जाना जाता था।

बेल-धातु, तांबा, पीतल आदि के सामान भारत के अधिकांश हिस्सों में उत्पादित किए गए थे, लेकिन सबसे उल्लेखनीय केंद्र बनारस, पूना, तंजौर, नासिक, अहमदाबाद और राजस्थान थे। सोने और चांदी में फिजी का काम, कलात्मक संगमरमर का काम, असाधारण कलात्मक रूपों में चाप्पल की लकड़ी की नक्काशी, हाथी दांत का काम और कांच का निर्माण और कई अन्य लेख, जैसे कि इत्र, पेपर-मेकिंग, टेनरी आदि भारत के महत्वपूर्ण उद्योग थे। तक “उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में जहाज निर्माण उद्योग इंग्लैंड की तुलना में भारत में अधिक विकसित हुआ था। भारतीय कपड़ा उद्योग की तरह, इसने अंग्रेजी निर्माताओं की ईर्ष्या को जन्म दिया और इसकी प्रगति और विकास कानून द्वारा

प्रतिबंधित थे”।

भारतीय व्यापार और उद्योग का क्षय उन्नीसवीं सदी के मध्य तक कमोबेश पूरा हो चुका था। क्षय के कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

- 1) ब्रिटिश संसद की नीति,
- 2) सर्स्टी मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा,
- 3) भारतीय कला और शिल्प को संरक्षित करने या प्रोत्साहित करने के लिए भारत में अंग्रेजी सरकार के इरादे की कमी,
- 4) भारतीय निर्माताओं, विशेषकर कंपनी के नौकरों द्वारा बुनकरों का विरोध,
- 5) कुछ लेखकों के अनुसार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और मशीनरी की मदद से भारी मात्रा में तैयार माल का उत्पादन और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कम लागत ने अंग्रेजी निर्माताओं को भारतीय निर्माताओं को रेखांकित करने में सक्षम किया, इस प्रकार भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन दूसरों की राय है कि इंग्लैंड में बहुत ही औद्योगिक क्रांति थी भारत की लूटी हुई संपत्ति का परिणाम, और भारत में अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए प्रयास नहीं किया था, लेकिन जानबूझकर उनके रास्ते में बाधाएं डालीं और कुछ मामलों में इंग्लैंड में उन लोगों के विकास में मदद करने के लिए भारतीय निर्माण को हतोत्साहित किया। रश-ब्रक विलियम्स की राय है कि यह उन दिनों के नेताओं में आधुनिक राज्य कौशल मान रहा होगा, अगर हम इंग्लैंड में उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय उद्योगों की उपेक्षा करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास करना चाहते थे।

लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों के ब्रिटिश राजनेताओं के पास आधुनिक अर्थशास्त्र के पर्याप्त विचार थे और वास्तव में भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगिता से कानून द्वारा अंग्रेजी उद्योगों की रक्षा की। भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए इसी तरह के कदम नहीं उठाए गए थे, क्योंकि वे राज्य की कमी के कारण नहीं थे, बल्कि भारतीय लागत पर अंग्रेजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासक अधिकारियों की इच्छा के कारण थे।

नया व्यापार पैटर्न- उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक, भारत ने यूरोपीय दुनिया में व्यापार और उद्योग में अपना वर्चस्व खो दिया, जिस गर्व की स्थिति में उसने लगभग दो हजार वर्षों तक कब्जा किया। वह अब कच्चे माल के उत्पादन के लिए एक देश में बदल गया था और इंग्लैंड में उत्पादित सस्ते मशीन-निर्मित माल के डंपिंग के लिए एक बाजार बन गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार जो लाखों भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदारी थी, उसने भारत को आपदा से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

अंग्रेजी कंपनी ने इंडिगो, जूट, चाय के साथ-साथ जूट वस्त्र, चीनी, कागज, खनन इत्यादि जैसे नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना शुरू किया और स्थापित उद्योगों की नकदी फसलों और उत्पादों के उत्पादन में व्यापार किया। पूंजी अंग्रेजों ने लगाई। नया व्यापार पैटर्न दो सिद्धांतों पर आधारित था, अर्थात् नकदी फसलों में व्यापार और कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत के रूप में भारत का इलाज करना और ऐसे उद्योग स्थापित करना जो इंग्लैंड के लोगों के साथ सीधे संघर्ष में नहीं थे और व्यापार को लाभ के रूप में प्राप्त करना था। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान।

फिर भी, यहाँ यह उल्लेख करना होगा कि अंग्रेजी के व्यापार का मुख्य उद्देश्य भारतीय धन का शोषण था।

अंग्रेजों के इस नए अधिग्रहीत क्षेत्र में भूमि निपटान की एक नई प्रणाली विकसित हुई। मद्रास में जायोटावारी सेटलमेंट नामक भूमि का निपटान थॉमस मुनरो के नाम के साथ समान रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे बाद में सर बनाया गया, क्योंकि लॉर्ड कार्नवालिस

का नाम बंगाल के जमीदारी सेटलमेंट से जुड़ा है। पूर्व में बोर्ड गए अनाज के आधार पर कार्नाटिक के राजस्व का नवाब साल दर साल बढ़ता गया। सर्वेक्षणकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए भूमि की माप की। लेकिन उन्होंने एक हजार धोखाधड़ी का अभ्यास किया और उनकी रिपोर्टों को उनके द्वारा प्राप्त रिश्वत द्वारा निर्देशित किया गया था।

जब क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है, तो राजस्व के निपटान के उद्देश्य से एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। राजस्व मंडल के कलेक्टरों और सदस्यों ने सार्वजनिक धन को लूट लिया, अर्थात्, राजस्व एकत्र किया, बिना किसी खतरे का पता लगाए। उन्होंने सरकार को वसूल किए गए वास्तविक किराए से नीचे का किराया दिया।

थॉमस मुनरो ने सबसे पहले बारमहल के रयोट्वरी सेटलमेंट को पूरा किया। इस प्रणाली में किराए को सीधे 60,000 किसानों, यानी रेयतों के साथ तय किया गया था। रयोतवारी सेटलमेंट का परिणाम सबसे उत्साहजनक था, पहले वर्ष में एकत्रित राशि के लिए 165,000 पगोडा थे, जिसमें एक भी रुपया बकाया नहीं था। प्रणाली जमीदारों के बजाय सीधे दंगों के साथ राजस्व का एक स्थायी समझौता था, अर्थात्, मध्यस्थी। बस्ती का यह स्थायित्व आवश्यक था, क्योंकि कृषि की उन्नति और लोगों की समृद्धि के लिए सरकार की माँग की शुद्धता होनी चाहिए। थॉमस मुनरो का रयोट्वरी सेटलमेंट स्थायी था, लेकिन खेती के लिए प्राप्त अतिरिक्त भूमि को अतिरिक्त राजस्व के अधीन किया जाना था।

मुनरो के रयोतवारी सेटलमेंट ने अधिकारियों के साथ पक्षपात किया और धीरे-धीरे कैनरा, मालाबार, तंजौर आदि को इस प्रणाली के तहत लाया गया और मालाबार के राजा और नायर चीफ, तंजौर के पट्टकार, आदि को भूमि बंदोबस्त के मामलों में रेयतों द्वारा बदल दिया गया।

रयोतवारी प्रणाली के पीछे असली मकसद राजस्व के आकार में भूमि से अधिकतम का एहसास करना था। कंपनी के निदेशकों में से एक ने टिप्पणी की, व्यह छुपाया या इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस (रयोतवारी) प्रणाली का उद्देश्य सरकार को यह प्राप्त करना है कि भूमि किराए के आकार में प्राप्त होगी। जमीदारों के साथ निपटान की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की गलत नीति के बारे में आरसी दत्ता ने कहा, "सही राजनेता ने चीजों के पुराने क्रम को जारी रखा होगा, और राजस और नायर प्रमुखों को ब्रिटिश सरकार और लोगों के नेताओं के वफादार विषयों में कम कर दिया। लेकिन कृषकों के साथ तुरंत बस्तियाँ बनाने की इच्छा, जिससे कि अधिक से अधिक राजस्व मिल सके, क्योंकि जमीन उपज सकती थी, कंपनी की सरकार की नीति को और अधिक प्रभावित करती थी, जैसे-जैसे वर्षों बीतते गए।

मद्रास प्रांत के लिए रैयतवारी प्रणाली को स्वीकार करने से पहले एक विस्तृत बहस हुई थी। विलियम बैंटिक ठीक उसी तरह का राय था जैसा मुनरो ने व्यक्त किया था, और यह दर्ज किया कि जमीदारी बस्ती बंगाल के अनुकूल है जहाँ बंशानुगत थे। जमीदार, लेकिन मद्रास के उन हिस्सों के अनुरूप नहीं थे जहाँ ऐसे जमीदार मौजूद नहीं थे।

मुनरो ने अलग-अलग रैयत के साथ एक समझौता किया, और यह चाहा कि यह स्थायी हो, राजस्व में वृद्धि या कमी के अधीन, कम या ज्यादा भूमि को खेती के तहत लिया गया था।

राज्यपाल ने कहा, व्यदि एक वार्षिक समझौता, निश्चित सिद्धांतों पर स्थापित किया गया था, जिसका अनिवार्य हिस्सा एक वर्ष के लिए अपने उद्योग के फल के लिए रैयत को सुरक्षित करना था, वास्तव में इस तरह के व्युत्पन्न फायदे के उत्पादक थे, एक स्थायी निपटान की स्थापना की। समान सिद्धांत, लेकिन रैयत के लाभ के संबंध में अधिक हद तक किए गए, एक समान अनुपात में एक ही प्रभाव पैदा करेंगे।

इस प्रकार दंगों के साथ स्थायी समझौता सीधे ब्रिटिश प्रशासकों का प्रमुख विचार था और मद्रास में रयोट्वरी सेटलमेंट पर

कार्वाई की गई थी।

थॉमस मुनरो ने किराये के मद्रास कल्टीवेटर फिक्स के लिए प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रूप से अपने सारे जीवन को बेकार कर दिया था, ताकि उनकी अपनी भूमि द्वारा किए गए सभी सुधार उनके स्वयं के लाभ होंगे। अतिरिक्त किराये का सवाल तब उठता है जब खेती के तहत ताजा जमीन लाई जाएगी। मुनरो के लंबे समय बाद 1855–56 की प्रशासनिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मद्रास रैयत को सरकार द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह निर्धारित मूल्यांकन का भुगतान करता है। सिस्टम के तहत रयोट वस्तुतः एक सरल और परिपूर्ण शीर्षक पर एक मालिक है, और एक सदा के पट्टे के सभी लाभ हैं। लेकिन रैयत का शीर्षक किसी उद्घोषणा या अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया था। 1857 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी उल्लेख किया कि— मद्रास रैयत मूल्यांकन के किसी भी वृद्धि के बिना अपनी भूमि को बनाए रखने में सक्षम है।

लेकिन इन सभी आश्वासनों और जोरदार शब्दों के बावजूद, प्रत्येक कृषक पर लगने वाले भूमि कर का निर्धारण प्रत्येक आवर्ती बस्ती में राजस्व अधिकारियों के विवेक पर किया जा रहा था। इस प्रकार वास्तव में मद्रास रैयत के पास न तो किराये की कोई निश्चितता थी और न ही वृद्धि के खिलाफ कोई सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से उसके अधीन भूमि के सुधार का कोई मकसद नहीं था। "भूमि कर की अनिश्चितता उसके सिर पर डमोकल्स की तलवार की तरह लटकी हुई है।"

1856 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने घोषणा की कि सरकार भू-राजस्व की हकदार नहीं थी और न ही किराए का जो उत्पादन की लागत (यानी, आर्थिक किराया) से अधिक अधिशेष था। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, चार्ल्स बुड ने सरकार की इच्छा को केवल एक हिस्सा लेने की घोषणा की, आम तौर पर टेंट का आधा हिस्सा भूमि कर के रूप में। किराए का आधा, यानी उत्पादन की लागत पर अधिशेष। खेती की एक छोटी सी लागत के लिए लगभग ख 7 या ख 8 था और सरकार ख 4 का दावा करेगी जो उत्पादन की लागत के ऊपर व्यावहारिक रूप से संपूर्ण अधिशेष थी।

इस प्रकार भूमि कर की अनिश्चितता और उत्पादन के कुल अधिशेष की सरकार द्वारा मांग ने स्वाभाविक रूप से काश्तकारों को बर्बाद कर दिया और उन्हें संसाधन—रहित बना दिया। लॉर्ड रिपन ने जिन परिस्थितियों में एक बार किराया निर्धारित किया, वह मूल्य वृद्धि के समतुल्य आधार को छोड़कर नहीं उठाया जा सकता था। इसने भूमि के राजस्व में वृद्धि के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया।

लेकिन दिसंबर, 1884 में रिपन ने भारत छोड़ दिया, जनवरी, 1885 में भारत के विदेश मंत्री ने समतामूलक नियम को रद्द कर दिया, जिसकी घोषणा रिपन ने की थी। इस प्रकार, भारत कार्यालय ने अपने असभ्य और परिणामस्वरूप भारतीय किसानों के प्रति विनाशकारी रवैया दिखाया। रैयतवारी बस्ती का प्रभाव यह था कि मद्रास काश्तकार अनिश्चित राज्य की मांग के बिना सुरक्षा के बिना छोड़ दिया गया था और इसलिए अपनी जमीन को सुधारने के लिए कोई भी मकसद नहीं बचा और उसके पास कोई संसाधन नहीं बचा।

जब उत्तरी भारत में भूमि ब्रिटिश शासन के अधीन लाई जा रही थी, स्वाभाविक रूप से भूमि बंदोबस्त का सवाल उठता था। कार्नवालिस और जॉन शॉर इन क्षेत्रों में स्थायी आधार पर जमीदारी बंदोबस्त का विस्तार करना चाहते थे जैसा कि 1793 में बंगाल में किया गया था। 1795 में पूरे बनारस में राजस्व का स्थायी निपटान किया गया था।

पुराने जमीदार जो बनारस के राजा के तहत अपने सम्पदा को खो चुके थे, उन्हें बहाल कर दिया गया और राजस्व स्थाई आधार पर गाँव जमीदारों के साथ उनके साथ ही बस गया। बंगाल, बिहार और उडीसा के लिए विनियम संहिता थोड़े से

परिवर्तन के साथ बनारस तक विस्तारित की गई थी और प्रशासित नागरिक और आपराधिक कानून बंगाल, बिहार और उड़ीसा में समान थे।

द कमिशनर, मेसर्स कोक्स और हेनरी सेंट जॉर्ज टकर ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थायी निपटान के कई लाभों को स्वीकार करते हुए खुद को उत्तरी भारत में इस तरह के निपटान के तत्काल निष्कर्ष के रूप में घोषित किया।

विशेष आयोग और सरकार के बीच एक दिलचस्प पत्राचार हुआ। आयोग ने कहा कि जब यह समझ में आया कि अस्थायी बस्तियां लोगों को परेशान कर रही थीं और उन्होंने धोखाधड़ी और अपशब्दों के लिए अवसरों की पेशकश की, तो यह नहीं सोचा था कि अगर सार्वजनिक कर में वृद्धि हुई तो देश में सुधार हो सकता है, और व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई अधिक से अधिक उद्योग के निष्पादन से किसी भी लाभ का आनंद लेने के लिए।

लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त से सहमत होकर अपने मुनाफे में संभावित वृद्धि का त्याग करने के लिए प्रभावित हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरी बार ऐसी उदारता के लिए दोषी बनने का मन नहीं किया और उनकी नीति अब घच्चतम राजस्व और क्रोध पर काबू पाने की थी। उन्होंने उत्तर दिया कि ‘कटक या हमारे प्रांतों में किसी भी बंदोबस्त को स्थायी घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके लिए पूरी कार्यवाही हमें सौंपी नहीं जाती है, और जब तक इन प्रस्तावों पर आपके प्रस्तावों को हमारी स्वीकृति और सहमति नहीं मिल जाती है’। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ महीने बाद लिखा, घर्तमान निराशा की वस्तु आपको हमारे नए अधिग्रहीत प्रदेशों के लिए बंगाल के निर्धारित मूल्यांकन के विस्तार के लिए हमें निवेदन करने के खिलाफ सबसे अधिक सतर्क तरीके से सावधान करना है।

गवर्नर-जनरल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रवैये पर आडे हाथों लिया गया, जो माप का एक आभासी परित्याग था जो भारत के लोगों के लिए बिल्कुल आवश्यक था और भारत के लोगों के लिए बिना शर्त दो बार घोषित किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जनादेश का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है?

एडम मिथर द्वारा राष्ट्र के धन में उल्लिखित आर्थिक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए और उत्तरी भारत में स्थायी समाधान की गुहार लगाते हुए लॉर्ड मिंटो द्वारा निदेशकों के न्यायालय में विरोध का एक और नोट प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मोटे थे और बताया कि—‘भारत के लोगों की भलाई की इच्छा अपने स्वयं के मुनाफे को आत्मसमर्पण करने से अधिक नहीं होगी’।

लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड मोइरा ने बाद में हेस्टिंग्स का मार्केस बना दिया था, लेकिन पिंडरी युद्ध, नेपाल युद्ध और साथ ही मराठा युद्ध में उनके ध्यान भंग होने के कारण उत्तरी भारत में राजस्व के स्थायी निपटान का सवाल कुछ समय के लिए अप्राप्य हो गया। जब विजय और देवदार जिलों में मराठा युद्ध आयुक्तों के बोर्ड के ऊपर था, अर्थात् उत्तरी भारत, जिसमें सर एडवर्ड कोलब्लक और श्री ट्राउट शामिल थे, ने मुरादाबाद, बरेली, शाजीपुर और रोहिलखंड और एक बार के जिलों के भूमि बंदोबस्त पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजस्व के स्थायी समाधान के लिए और अधिक दबाया गया।

सरकार ने राजस्व के स्थायी बंदोबस्त के राजकोषीय लाभों पर कोई चर्चा किए बिना, 1802 और 1805 के अपने नियमों में सरकार द्वारा दिए गए पूर्ण प्रतिज्ञाओं के निदेशकों के न्यायालय को फिर से लिखा। श्री डोवेलवेल ने भारत से अपने सेवानिवृत्त होने की पूर्व संध्या पर एक लंबे समय तक प्रतिष्ठित सेवा के लिए बिना किसी अनिश्चित शब्दों के बात की। स्थिति, तब, जिसे मैं बनाए रखता हूँ, यह है कि सरकार के विश्वास को लोगों के महान निकाय को स्थायी रूप से निपटान के लाभों को देने के लिए प्रतिज्ञा की गई थी।

‘एक व्यापारिक कंपनी के निदेशक, जो अब एक साम्राज्य के मालिक हैं, ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रस्तावों को एक जिज्ञासा के

साथ मना कर दिया, जिसमें विश्वास दिलाया गया था कि जब वे अपने स्वयं के हितों की चिंता करते थे, तो लोगों की खुशी के लिए वे कितना वास्तविक संबंध रखते थे’। एक स्थायी निपटान के सभी विचारों को इस प्रकार 1921 में समाप्त कर दिया गया था अंत में बस्तियों को जर्मींदारों के साथ बनाया गया था जहां वे मौजूद थे और ग्राम समुदायों के साथ जहां उन्होंने सामान्य किरायेदारी में भूमि का आयोजन किया था। बस्ती का पुनरीक्षण गाँव को गाँव और संपदा द्वारा गाँव बना दिया गया था और एक संपत्ति के रूप में भारतीय भाषा में एक महल कहा जाता था, उत्तर भारत में बस्ती को कहा जाता है महल-वारि बस्ती।

भारत में कृषि समाज पर ब्रिटिश भूमि प्रणाली का प्रभाव— जर्मींदारी और रयोटवारी बस्तियों के मामलों में ब्रिटिश राजस्व निपटान का प्रभाव कुछ अलग था। जिन क्षेत्रों में जर्मींदारों के साथ एक स्थायी समझौता किया गया था, वहाँ भूस्वामी वर्ग के चरित्र में काफी बदलाव आए, जिसने किसान पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी।

जर्मींदारी प्रणाली के कारण गैर-ग्रामीण और अनुपस्थित जर्मींदारों में वृद्धि हुई और जर्मींदारों और काश्तकारों के बीच संबंध खराब हो गए। भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन से खेती का क्षेत्र तेजी से बढ़ा लेकिन किसानों को खुद किसी भी तरह से फायदा नहीं हुआ।

निष्कर्ष

जर्मींदारी प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव जर्मींदारों द्वारा बड़े और बड़े सम्पदा का अधिग्रहण करने की प्रवृत्ति थी, जो मुख्य रूप से बेदखली के कारण भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन ब्रिटिश राजस्व निपटान का सबसे गंभीर प्रभाव यह था कि इसने मौजूदा कृषि तकनीकों को रेखांकित करने में मदद की और यह उन्नीसवीं सदी के मध्य तक नहीं था कि सरकार ने इस संबंध में कुछ भी किया।

रयोटवारी बंदोबस्त के तहत भी समान परिणाम देखे गए क्योंकि जर्मींदारी बंदोबस्त के मामले में निर्दिष्ट राजस्व के भुगतान की विफलता पर तुलनात्मक रूप से छोटी संख्या को छोड़कर। भारत के विभिन्न हिस्सों के कृषि समाज पर समग्र प्रभाव उच्च मूल्यांकन, धन के संचय के अवसर की कमी और। कृषि के किसी भी सुधार के लिए पहल करना। कृषि पिछड़ी रही, कृषक गरीब होते चले गए, भूमिहीन मजदूर समय की प्रगति के साथ बढ़ते गए, अनुपस्थित जर्मींदारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ भी धन का उत्पादन किया, उसे छोड़ दिया, जिससे कृषि समाज एक दयनीय अस्तित्व में आ गया।

संदर्भ

1. विल किमलिका, “कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी—एन इंट्रोडक्शन”, ऑक्सफोर्ड प्रेस, लंदन, वर्ष 1990.
2. ओ.पी. गाबा, “एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी”, मेकमिलन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, वर्ष 2003.
3. रजनी कोठारी, “रिथिकिंग डेवलपमेंट—इन सर्च ऑफ ह्यूमन अल्टरनेटिव”, अजंता पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, वर्ष 1988.
4. डेनियल बेल, “पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी” रूटलेज पब्लिशर्स, लंदन, वर्ष 1999.
5. विपीन चन्द्रा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हि.मा.कार्या.निदे., 1995, नई दिल्ली
6. बी.एल. गोयल, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द्र, 1981
7. बिपिन चन्द्र 1979, नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉर्डन इंडिया